have been forwarded to the Centre for special assistance for the development of Eastern Ghats and Coastal Areas at a cost of Rs. 411 crores and Rs. 265.50 crores respectively. As the fiscal rating of Tamil Nadu is the best in the country, I appeal to the Centre to clear all these projects relating to Tamil Nadu and provide funds as demanded.

Need for providing better equipment and Clothing, to Soldiers posted at Siachen and Kargil frontiers

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, we all acclaim the sacrifices made by our courageous soldiers at Saltoro Ridge overlooking Siachen, Hanif, Yaldor Sectors in Kargil and other frontiers of India where temperature goes down to -40 to -50 degrees. At the same time we are equally responsible for the pathetic conditions in which they have to guard our borders. They are performing their duty with old, torn, obsolete clothing in chilly 16,000 feet height Indian border. A proposal has been submitted for three sets of specialised clothing — one for troops posted there, one for soldiers to get acclimatize and the other for outfit soldiers who may have to rush in case of emergency — but the proposal is hanging fire. The problem is, so cruel are the conditions that barely 15% of the clothing and snow-boots can be reused. Then, many of these clothing such as Pitons, Carabineers, Down Jackets, Multi-tiered Insulating Gloves, Special Trousers, Woolen Socks, Goggles, Gore-Tex suit come from Switzerland, Boot Crampons, Rucksacks, Special Boots from Central Europe and Sleeping Bags from Belgium. If the Government shows any lethargy, things will go from bad to worse. Even the Subramanyaswami Committee recommended that priority should be given to equipping infantry men with superior equipment and clothing. Recently, I had personally seen the pathetic conditions under which our soldiers have to work at Siachen and Kargil. Hence, I demand that immediate steps should be taken and the equipments that I mentioned should be procured within no time and be supplied to the Army immediately. Thank you.

Demand for a regulator for electronic media to regulate Nude, Vulgar and Obscene advertisements responsible for crimes including rape of girl child

श्रीमती कुमकुम राय (बिहार): उपसभापति महोदय, आजकल नन्हीं बच्चियों से बलात्कार की घटनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। कुछ माह से लेकर दो-चार साल तक की लड़कियों को हैवानियत का शिकार बनाया जा रहा है। बलात्कार की शिकार बच्चियों की हत्या की संख्या भी बढ़ रही है। रिश्तेदारों या पड़ोसियों द्वारा दुष्कर्म करने के लिए इन बच्चियों को सॉफ्ट टारगेट के रूप में सहज-सुलभ रूप में देखा जा रहा है। इन दुष्कर्म की वारदातों के बाद हाय-तौबा मचाना या कागजी खानापूरी करना और बात है। इस सामाजिक बुराई या अपराध के कारणों की पड़ताल

करके निदान खोजना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन और इन्टरनेट पर कामुकता बढ़ाने वाले नृत्यों और चित्रों की भरमार है। रिमिक्स अलबम के नाम पर सभी चैनल इन अश्लील नृत्यों को दिखा रहे हैं। इन नृत्यों में कम से कम कपड़े पहने नर्तकियां कामुक भाव-भंगिमा और नंगेपन का अत्यंत भद्दे ढंग से प्रदर्शन करती हैं। ऐसे भड़काऊ एवं कामोत्तेजक नृत्य इन दुष्कर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं।

महोदय, अपसंस्कृति के वाहक ये प्रोग्राम हमारी भावी पीढ़ी को खतरनाक ढंग से प्रभावित कर रहे हैं। अत: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अधिकार संपन्न एक नियामक तंत्र बनाने की जरूरत है, जो विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए मार्गनिर्देश बना सके और सख्ती से इनका पालन करवा सके। चूंकि अब डी.टी.एच. का ज़माना आ रहा है, अत: अब देश-विदेश के तमाम चैनल घर बैठे देखे जा सकेंगे। इसलिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दूषित करने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक समझा जा रहा है। अत: सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अतिशीघ्र एक सक्षम नियामक तंत्र बनाए और उसे कार्यान्वित करे।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं अपने को इस स्पैशल मैंशन से संबद्ध करती हूं।

श्री जयन्तीलाल बरोट (गुजरात): महोदय, मैं अपने को इस स्पैशल मैंशन से संबद्ध करता हूं।

श्री जय राम रमेश (आंध्र प्रदेश): महोदय, मैं अपने को इस स्पैशल मैंशन से संबद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Janardhana Poojary. Absent.

श्री अबू आसिम आज़मी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

†[شری ابوعاصم اعظمی (اتر پردیش): اپ سبھاپتی مہودے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ......مداخلت......]

उपसभापति: अभी स्पैशल मैंशन चल रहे हैं, There is no other subejct except the Special Mentions which is being discussed right now. (*Interruptions*)

श्री अबू आसिम आज़मी: मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा आपका। बाबरी मस्जिद के इस मुद्दे को हम बार-बार उठाना नहीं चाहते लेकिन ...(व्यवधान)

†[شری ابوعاصم اعظمی: میں صرف ایک منٹ لونگا آپکا۔ بابری مسجد کے اس مدّے کو ہم بار بار اٹھانا نہیں چاہتے لیکن......مداخلت......]

उपसभापति: आपने नोटिस नहीं दिया है ...(व्यवधान) आपने नोटिस नहीं दिया है, प्लीज ...(व्यवधान)

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

श्री अबू आसिम आज़मी: महोदय, देश के करोड़ों लोगों ...(**व्यवधान**)

†[ ] شری ابوعاصم اعظمی : مہودے، دیش کے کروڑوں لوگوں.....مداخلت.....]†

उपसभापति: आपने नोटिस नहीं दिया है, चेयरमैन की इज़ाज़त नहीं ली है, I will not allow that ...(*Interruptions*)

श्री अबू आसिम आज़मी: अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था कि ...(**व्यवधान**) मैं एक मिनट लूंगा ...(**व्यवधान**)

†[ ] شری ابوعاصم اعظمی : ابھی حال ہی میں اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی نے جو بیان دیا تھا کہ .....مداخلت..... میں ایک منٹ لونگا.....مداخلت.....]†

उपसभापति: आपने नोटिस नहीं दिया है, नोटिस की जरूरत है ...(**व्यवधान**) आपको चेयरमैन की इज़ाज़त लेनी चाहिए थी, I will not allow that ....(*Interruptions*) आपने इज़ाज़त नहीं ली है, इसलिए मैं इज़ाज़त नहीं दूंगा ...(**व्यवधान**) Now, the hon. Home Minister to introduce the Bill.

GOVERNMENT BILLS—*Introduced*

THE DISPLACED PERSONS CLAIMS AND OTHER LAWS REPEAL BILL, 2004

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिक राव गावित): उपसभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विस्थापित व्यक्ति दावा अधिनियम, 1950 और कुछ अन्य अधिनियमनों का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री माणिकराव गावित: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

THE CREDIT INFORMATION COMPANIES (REGULATION) BILL, 2004

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation of credit information companies and to facilitate efficient distribution of credit and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I introduce the Bill.

---

†[ ]Transliteration in Urdu Script.